



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 146]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 1984/आश्विन 28, 1906

No. 146]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 1984/ASVINA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 59-आई टी सी (पी एन)/84

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1984

विषय :—अप्रैल 1984—मार्च 1985 के लिए आयात-  
निर्यात नीति।

मिसिल सं. 12/44/84-ई पी सी:—वाणिज्य मंत्रालय की  
सार्वजनिक सूचना सं० 18-आई टी सी (पी एन)/84 दिनांक  
12 अप्रैल, 1984 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल 1984-मार्च,  
1985 के लिए यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की  
ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपायुक्त  
स्थानों में किए गए समझे जायेंगे :

क्रम	आयात-निर्यात	संदर्भ	संशोधन
सं०	नीति 1984- 85 (जिल्द 1) की पृष्ठ सं०		
1	2	3	4
1	55	अध्याय 17 पैरा 168	वर्तमान उप-पैरा (3) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा (4) ओर (5) जोड़ा जाएगा: “(4) स्वर्ण आभू- षण के निर्माण के लिए विशेष निर्यात अभिमुख फम्प्लैक्स स्थापित करने के लिए एक योजना

1	2	3	4
			घोषित की गई है। योजना का व्योरा परिशिष्ट 22 के अनुबन्ध 4 में दिया गया है। (5) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्वर्ण आभूषण के निर्माण के लिए एक योजना घोषित की गई है। योजना का व्योरा परिशिष्ट 22 के अनुबन्ध 5 में दिया गया है।”
2.	348	परिशिष्ट 22	परिशिष्ट 22 के अनुबन्ध 4 के बाद प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना से यथा संलग्न अनुबन्ध 5 “मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्वर्ण आभूषण के निर्माण के लिए योजना” को जोड़ा जाएगा।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

परिशिष्ट-22

अनुबन्ध-5

मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण के लिए योजना।

मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण के लिए स्वीकृति दी जाएगी। मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण के लिए स्थित एकक को छोड़ते हुए इस नीति के परिशिष्ट 15 में यथा दर्शाए गए मुक्त व्यापार क्षेत्र योजना के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे :—

(1) रह कर दिए गए माल सहित इन कम्प्लैक्स में विनिर्मित किसी भी माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी,

(ख) आभूषण के विनिर्माण एककों की विशेष आवश्यकताओं जिनमें मशीनरी, उपकरण, उपभोग्य और अनुषंगी उपकरण शामिल हैं, का सुनिश्चय बनाई जाने वाली मर्चों की सूची में से प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाएगा,

(ग) एक ऐसा एकक जिसमें अपना कार्य बन्द कर दिया है तो उस स्थिति में आभूषण के लिए उपलब्ध स्वर्ण, अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रित धातु, रत्न और अन्य सामान उस अभिकरण द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली कीमत पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मनोनीत किए गए अभिकरण को सौंप दिए जायेंगे। ऐसे अभिकरण की पहचान वाणिज्य मंत्रालय करेगा और उपयुक्त अधिसूचना जारी करेगा।

(घ) ऐसे एकक में उत्पादन के लिए 30 प्रतिशत या इससे अधिक की जोड़ी गई न्यूनतम मूल्य वस्तु का होना आवश्यक होगा।

2. आरम्भ में ऐसे एककों को फाल्टा, मद्रास, कोचीन और नोयडा में स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्रों के लिए अनुमति दी जाएगी।

3. अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्रों में ऐसे एककों को स्थापित करने की सुविधा को बढ़ाने का निर्णय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बाद में लिया जाएगा।

4. इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वर्ण आभूषण के विनिर्माणिक एककों के मामले में, पूंजीगत माल, आदि रुपों, तकनीकी नमूनों, उपभोग्य फालतू पुर्जों और पैकेजिंग माल के आयात के लिए अनुमति की जाने वाली सुविधाओं पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अलग से विचार किया जाएगा और अलग से एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

5.1 इन क्षेत्रों के एककों को निर्यात संबद्धन परिषद योजना के लिए लागू क्रियाविधि और नीचे की कड़िका 6 में निर्धारित शर्तों के अनुसार, सभी प्रकार के कच्चे माल, मध्यस्थ और संघटकों जिनमें मिश्रित सोना, कैरट सोना, रंगीन सोना, बहुमूल्य धातु जिसमें प्लेटिनम और प्लेडियम शामिल हैं, साकेट, फ्रेम्स, माउन्टिंग, रत्न और पत्थरों के सीधे आयात के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.2 लेकिन, 0.999 फाइननेस और शुद्धता वाले सोने के लिए, स्वर्ण नियंत्रक प्राधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड एवं मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के साथ परामर्श करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मनोनीत किसी भी अभिकरण के माध्यम से किए गए निर्यातों को छोड़कर अन्य के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में बम्बई में स्थित सरकारी टंकाल द्वारा विशेष पहचान चिन्ह लगाया जाएगा।

6. एक विशेष एकक द्वारा विनिर्माण के लिए अपेक्षित आयातित माल की मात्रा के संबंध में निर्धारण, संभावित निर्यात और एकक द्वारा संकेतित और अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापार चक्र के अनुसार उसकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। आरम्भ में

नुनिश्चित की गई मात्रा की सीमाओं को, निर्यात आयुक्त या अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुनः निर्धारण के लिए मनोनीत किसी भी अधिकारी की सिफारिश के आधार पर स्थापित निर्यात निष्पादन, वर्तमान आदेश और उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

7. आभूषण क्षेत्रों में प्रचालन के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित एककों के लिए स्वर्ण निर्यात अधिनियम के अधीन व्यापारी लाइसेंस एककों द्वारा प्राप्त किए जायेंगे।

8. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता शुरू-शुरू में इस योजना में भाग लेने के लिए एक पूर्व अपेक्षित शर्त नहीं होगी किन्तु उन्हें चाहिए कि वे प्रथम निर्यात की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर हो उसमें शामिल हो जाएं।

9. इस योजना के अधीन निर्यात की स्वीकृति केवल वायुयान द्वारा सीमा शुल्क सदन, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और कोचीन के माध्यम से ही दी जाएगी।

#### MINISTRY OF COMMERCE

#### IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 59—ITC(PN)/84

New Delhi, the 10th October, 1984

Subject : Import and Export Policy for April 1984-March 1985.

F. No. 12/44/84-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984—March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:

Sl. No.	Page No. of Import & Export policy, 1984 85 (Vol. I)	Reference	Amendment
---------	--	-----------	-----------

1	2	3	4
1.	55	Chapter 17 Para 168	After the existing sub-para (3) the following sub-paras (4) and (5) will be added:— “(4) A scheme for setting up special export oriented complexes for manufacture of Gold Jewellery has been announced. Details of the Scheme have been provided in Annexure IV to Appendix 22.

1	2	3	4
			(5) A Scheme for manufacture of Gold Jewellery in Free Trade Zones has been announced. Details of the Scheme have been provided in Annexure V to Appendix 22.”
2.	348	Appendix 22	After Annexure IV to Appendix 22, Annexure V Scheme for manufacture of Gold Jewellery in Free Trade Zones as annexed to this Public Notice, shall be added.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

#### APPENDIX 22

#### ANNEXURE-V

#### Scheme For Manufacture of Gold Jewellery in Free Trade Zones.

Manufacture of gold Jewellery will be permitted in FTZs. Units set up in FTZs. for manufacture of gold jewellery will be governed by the provisions of the FTZ scheme as detailed in Appendix 15 of this Policy, except that :

- nothing, including the rejects, manufactured in these complexes will be permitted to be sold in the domestic tariff area;
- the specific requirements of jewellery manufacturing units, including machines, equipment, consumables and ancillaries will be determined on a case by case basis, from a list of items which will be drawn up;
- in the event of a unit ceasing its operations, gold, other precious metals, alloys, gem and other material available for manufacture of jewellery will be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce at the price to be determined by that agency. Ministry of Commerce will identify such an agency, and issue appropriate notification.
- minimum value added content of 30% or more will be necessary for production in such a unit.

2. To start with, such units will be permitted in the FTZs at FALTA, Madras, Cochin and NOIDA.

3. The decision to extend the facility of setting up such units at other FTZs will be taken subsequently by the Ministry of Commerce.

4. In the case of gold jewellery manufacturing units operating in these Zones, the facilities to be allowed for import of capital goods, prototypes, technical samples, consumables, spares and packaging material will be separately worked out as approved by the Board of Approvals, and a separate notification will be issued.

5.1 The units in these Zones will be permitted in accordance with the procedure applicable to the EPZ scheme and the stipulation laid down in para 6 below, to directly import all raw materials, intermediates and components, including gold alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including platinum and palladium, sockets, frames, mountings, gems and stones.

5.2 Gold of 0.999 fineness and purity will, however, not be allowed except through the State Bank of India or any other agency designated by the Ministry of Commerce in consultation with the Gold Control authorities, the Central Board of Excise and Customs and the Chief Controller of Imports and Exports and, in such cases, special identification marks will be stamped by the Government Mint at Bombay.

6. The assessment about the quantity of imported material required for manufacture by a particular unit will be determined on the basis of the potential of export and its periodical requirement according to a cycle of turnover indicated by a unit and

approved by the Board of Approvals. The limits of quantities determined initially may be reduced or enhanced by the Board of Approvals in the light of export performance, orders in hand or the capacity of production, established on the basis of the recommendations of the Export Commissioner or any other officer designated for re-assessment by the Board of Approvals.

7. Dealers' licences under the Gold Control Act for units approved by the Board of Approvals for operation in jewellery Zones will be obtained by the units.

8. Membership of the Gem and Jewellery Export Promotion Council will not be a pre-requisite condition to participate in the Scheme to begin with but they should join the Council within a period of three months from the date of first export.

9. Export under this scheme shall be allowed only by air freight through the Customs House at Bombay, Calcutta, Madras, Delhi and Cochin.